



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 आश्विन 1937 (श10)

(सं0 पटना 1169) पटना, वृहस्पतिवार, 8 अक्टूबर 2015

सं0 08/आरोप-01-112/2014-सां०प्र०-12508
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

25 अगस्त 2015

श्री ब्रह्मी राम, बि0प्र0से0, (कोटि क्रमांक-439/11) तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी नवहट्टा, सहरसा (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक-151 दिनांक 06.02.2012 द्वारा छात्रवृत्ति की राशि के वितरण में अनियमितता बरतने के लिए आरोप प्रपत्र 'क' गठित कर उपलब्ध कराया गया। प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में श्री राम से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-15325 दिनांक 07.11.2012 द्वारा जिला पदाधिकारी, सहरसा से मंतव्य की मांग की गयी जो उनके पत्रांक-12 दिनांक 24.01.2013 द्वारा उपलब्ध कराया गया।

2. उक्त आलोक में मामले की समीक्षा के उपरांत श्री राम के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-9582 दिनांक 20.06.2013 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 (2) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। जाँच पदाधिकारी, प्रधान सचिव-सह-अपर विभागीय जाँच आयुक्त, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-14 दिनांक 05.02.2015 द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध गठित कुल 07 आरोपों में से आरोप सं0-6 एवं 7 को छोड़कर सभी को प्रमाणित अथवा आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया। जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुये विभागीय पत्रांक-3231 दिनांक 27.02.2015 द्वारा श्री राम से लिखित अभ्यावेदन की मांग की गयी, जो उनके पत्रांक-कैम्प-01, दिनांक 14.03.2015 द्वारा उपलब्ध कराया गया।

3. श्री राम के विरुद्ध मुख्य आरोप नवहट्टा प्रखंड पदस्थापन काल में वर्ष 1995-99 की अवधि के लिए आवंटित छात्रवृत्ति की राशि कुल रूपये 4,27,780.00 (चार लाख सत्ताईस हजार सात सौ अस्सी रूपये) में से एक मुश्त चार लाख रूपये तत्कालीन पंचायत सेवक श्री नन्द किशोर यादव को वितरण हेतु अग्रिम स्वरूप दिये जाने का है। आरोपित पदाधिकारी के द्वारा राशि वितरण का अनुश्रवण नहीं किये जाने के कारण यह राशि वर्ष 2002 तक पंचायत सेवक के पास अव्यवहृत पड़ी रही। बाद में फर्जी अविवश्रव पारित कर राशि को समायोजित किया गया, जो गबन का मामला है।

4. जाँच प्रतिवेदन के आलोक में समर्पित लिखित अभ्यावेदन में आरोपित पदाधिकारी श्री ब्रह्मी राम ने मुख्य रूप से स्पष्ट किया की उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी, नवहट्टा, सहरसा का अतिरिक्त प्रभार दिनांक 08.12.2000 को ग्रहण किया था। चूँकि 31 मार्च तक की गयी निकासी की राशि को उसी वित्तीय वर्ष में वितरित करना संभव नहीं

था इसलिए उन्होंने रुपये 4,00,000.00 (चार लाख) को उसी दिन नाजीर को दे दिया जिसका वितरण अगले वित्तीय वर्ष में किया जाना था। लेकिन पंचायत सेवक द्वारा इसका वितरण नहीं किया गया।

5. आरोपी पदाधिकारी श्री ब्रह्मी राम के विरुद्ध गठित आरोप, जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं उनके द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा के उपरांत पाया गया है कि :-

(i) वर्ष 1995-99 तक की अवितरित छात्रवृत्ति की राशि को इतने दिनों बाद वितरित किया जाना प्रासंगिक नहीं था।

(ii) पंचायत सेवक ने इस राशि का वितरण किया है या अथवा नहीं इसकी खोज खबर अपने पदस्थापन के दौरान आरोपित पदाधिकारी द्वारा नहीं ली गयी और न ही वितरण का अनुश्रवण ही किया गया।

(iii) वितरण की सूची, जिसे अभिश्रव के रूप में बिना जाँचे श्री राम द्वारा पारित किया गया, वह जाँच में फर्जी पाया गया। अन्ततः राशि की वसूली के लिए प्राथमिकी दर्ज की गयी एवं पंचायत सेवक के सेवान्त लाभ से वर्षों बाद इस राशि की वसूली की गयी।

6. उक्त समीक्षात्मक तथ्यों के आलोक में संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए सम्यक् रूप से विचारोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया कि बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी०) के तहत श्री ब्रह्मी राम, बि०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-439/11) तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी नवहट्टा, सहरसा (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के पेंशन से 20 प्रतिशत की कटौती 10 वर्षों के लिए की जाय।

7. विभागीय पत्रांक-6108, दिनांक 22.04.2015 द्वारा श्री ब्रह्मी राम के विरुद्ध अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उक्त विनिश्चित निर्णय पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की माँग की गयी। आयोग के पत्रांक-1284, दिनांक 11.08.2015 द्वारा अनुशासनिक प्राधिकार के उक्त निर्णय से सहमति व्यक्त की गयी है।

8. वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्री ब्रह्मी राम, बि०प्र०से०, (कोटि क्रमांक-439/11) तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी नवहट्टा, सहरसा (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के पेंशन से 20 प्रतिशत की कटौती 10 वर्षों तक किये जाने का निर्णय संसूचित किया जाता है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
केशव कुमार सिंह,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1169-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>